उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 13 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(07/60)

प्रभारी सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी ने जानकारी दी कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान स्थानान्तरण सत्र हेतु वार्षिक स्थानान्तरण की समयावधि 20 जुलाई, 2017 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। प्राप्त निदेशों के क्रम में उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव एवं विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष 20 जुलाई 2017 तक वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 13 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(07/59)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में समस्त जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। लगभग 5 घण्टे चली मैराथन समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन, विकास योजनाओं, शहरी स्वच्छता, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल संचय, तहसील दिवस, समाधान पोर्टल, कानून व्यवस्था, चार धाम यात्रा, काँवड, बायोमैट्रिक हाजिरी, कार्य संस्कृति में सुधार, स्थानीय लोगों एवं किसानो की आजीविका में वृद्धि जैसे कई मुद्दों पर समीक्षा की।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बायोमैट्रिक हाजिरी, जल संचय, हरेला जैसे मुद्दों पर जिलाधिकारी नैनीताल को रिपोर्टिंग और कार्य में सुधार लाने की नसीहत भी दी।

आपदा प्रबन्धनः अधिकारी 24 घण्टे 'रेडी–मोड' मे रहें– सीएम

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि शहरी क्षेत्रों में तीव्र प्रवाह की जल निकासी की व्यवस्था के लिए ठोस उपाय किये जाए। सार्वजनिक मार्गों एवं नालों पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाय। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जिलाधिकारियों से पूछा कि बाढ़ चौकियों की क्या स्थिति है ? उन्होने सभी बाढ़ चौकियों को आपदा प्रबंधन के उपकरणों से लैस करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही सभी नदियों की लगातार गहन मॉनिटरिंग भी करने के निर्देश दिये। उन्होने जिलाधिकारियों से कहा कि खतरे के स्थान के बेहद नजदीक पहुँच चुकी नदियों के निकट की आबादियों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने की योजना तैयार रखे।

दैवीय आपदा में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में सभी जिलाधिकारी तत्परता दिखाए। आपदा में जनहानि की दशा में 24 घंटे के भीतर सहायता देने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में चेताया कि सहायता राशि की स्वीकृति मात्र से काम नहीं चलेगा, लोगों को सहायता मौके पर अतिशीघ्र मिलनी चाहिए। इस मामले में कोई कोताही स्वीकार नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को 24 घण्टे 'रेडी मोड' में रहने को कहा है। सभी सरकारी कार्मिक अपना मोबाइल 24 घण्टे खुला रखें। आपदा में रिस्पांस टाइम में सुधार हुआ है परन्तु इसे और बेहतर करने की जरूरत है। राहत शिविरों की स्थापना की तैयारी में और प्रभावी कार्य की जरूरत है। सभी डीएम आपदा प्रबन्धन से जुडे उपकरण, टेण्ट इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित रखें। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से पहाड़ो में कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने पहाड़ों में मोबाइल टावर नहीं लगाने वाली कम्पनियों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में केबल बिछाने की और अन्य अनुमतियां तभी दी जाएगी जब ये मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियाँ पर्वतीय भागों में अपनी कनेक्टिविटी का कमिटमेंट पूरा करेंगी ।

जिलाधिकारी नैनीताल ने अवगत कराया कि वर्षा ऋतु में नैनी झील अपने सामान्य स्तर पर पहुँच गयी है। मुख्यमंत्री ने सूखा ताल में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण पर हुए नाराजगी व्यक्त की। जिन लोगों को विस्थापित किया जाना हो तत्काल करे। उन्होने जिलाधिकारी नैनीताल को तत्काल कड़ी कार्यवाही करने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने जिला प्रशासन देहरादून से पूछा कि हाल की भारी वर्षा के कारण जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिला प्रशासन द्वारा उन गांवों में खाने–पीने तथा चिकित्सा सुविधाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है ? क्या अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है?

सेवाओं की पब्लिक डिलीवरी में तेजी लाये– सीएम

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सभी जिलाधिकारियों को कार्य संस्कृति में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी को तहसीलों और ब्लाकों तक पहुँचाए जाए। अधिकारी कर्मचारी सिर्फ समय पर ही न पहुँचे बल्कि जनता का काम भी करे । जनता को कार्य संस्कृति में सुधार दिखना चाहिए। जिलाधिकारी सभी कार्यालयों में फाइल मूवमेंट और जनता की समस्याओं के निस्तारण की भी समीक्षा करें। तहसील दिवस और समाधान पोर्टल पर जिलाधिकारी विशेष ध्यान दें। उन्होने सभी जनपदों में तहसील दिवस में आने वाले लोगों की कम संख्या पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसके व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। जनपदों में ही समस्याओं का निस्तारण हो जाय, लोगों को लम्बा सफर कर देहरादून तक आने की जरूरत न हो। पब्लिक डिलीवरी सिस्टम कैसे तेज हो इस पर ध्यान दें।

मुख्यमंत्री ने नैनीताल में वन विभाग में मशीन व बायोमैट्रिक हाजिरी न होने पर एक हफ्ते का चेतावनी दी है। उन्होने नैनीताल में बायोमैट्रिक हाजिरी की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को एक हफ्ते में सभी कार्यालयों को बायोमेट्रिक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करे। दूरस्थ स्थानों में तीन से छः माह तक का खाद्यान्न रखें। बागेश्वर में खाद्यान्न भंडारण के किए गोदाम की स्थिति ठीक नहीं है, जिलाधिकारी ने गोदामों की मरम्मत के लिए धन की माँग की। कांफ्रेसिंग में जिलाधिकारी हरिद्वार ने बताया कि हरिद्वार में ४२ लाख कांवड़िये आ चुके हैं। तथा कांवड पट्टी का काम पूरा हो चुका है। विद्युत व्यवस्था जलापूर्ति, कानून व्यवस्था ठीक है।

उत्तराखण्ड के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लायें– सीएम

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने स्वच्छता की अखिल भारतीय रैंकिंग में उत्तराखंड के शहरों व कस्बों की रैंकिंग एक वर्ष में शीर्ष 150 के भीतर लाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को लक्ष्य दिया है। उन्होने निर्देश दिए कि शहरी स्वच्छता अभियान की जिलाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा करें। दिसम्बर तक सारे नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा उठाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि शहरी स्वच्छता के नोडल अधिकारी जिलाधिकारी होंगे। सभी एस0डी0एम0/संयुक्त मजिस्ट्रेट को उनके क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति भी जवाबदेह बनाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सम्बंधित एस0डी0एम0/संयुक्त मजिस्ट्रेट की चरित्र पंजिका में उनके प्रयास दर्ज किए जाएँगे। उन्होने कहा कि नैनीताल, कठगोदाम, हल्द्वानी स्वच्छता रैंकिंग में काफी नीचे है। इस सम्बंध में जिलाधिकारी स्पेशल ऐक्शन प्लान बनाए।

शहरों में देहरादून 316 वी रैंक पर है। जिलाधिकारी, देहरादून में स्वच्छता अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करें। अधिशासी अधिकारी (ई0ओ0) अपने तैनाती स्थान पर ही निवास करें। एक वर्ष के भीतर देहरादून को शीर्ष 100 में लाने का तात्कालिक लक्ष्य, और फिर शीर्ष 50 शहरों में लाने का लक्ष्य रखा जाय। डोर टू डोर कलेक्शन और नगर निकायों में यूजर चार्जेज निर्धारित किया जाय। ट्रेंचिंग ग्राउंड सभी जगहों पर जरूरी हैं। इस सम्बंध में जिलाधिकारी प्रस्ताव भेजें और वन विभाग कार्यवाही करे।

प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण आवास योजना में लाभार्थियों को भूमि देने का सर्वे तय समय सीमा में किया जाय। जिन जिलाधिकारियों ने सर्वे शुरू नहीं किया है तुरंत शुरू करें। ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार जनपद को सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।

चमोली में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालयो के लिये कुल 2811 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 1348 निर्माणाधीन हैं। बागेश्वर में 936 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 626 निर्माणाधीन हैं। उधमसिंहनगर में 3150 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 964 निर्माणाधीन है। जिस पर तेजी की आवश्यकता है। देहरादून में 2453 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 989 निर्माणाधीन है। हरिद्वार में 3171 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 704 निर्माणाधीन है। उत्तरकाशी में 579 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 116 निर्माणाधीन है। टिहरी गढ़वाल में 282 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 82 निर्माणाधीन है। रूद्रप्रयाग में 219 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 05 निर्माणाधीन है। पौड़ी गढ़वाल में 415 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 123 निर्माणाधीन है। पिथौरागढ़ में 796 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 463 निर्माणाधीन है। अल्मोड़ा में 121 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 42 निर्माणाधीन है। चम्पावत में 384 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 190 निर्माणाधीन है। नैनीताल में 1463 सत्यापित आवेदनों के सापेक्ष 992 निर्माणाधीन है। पूरे प्रदेश में 27685 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें 16780 सत्यापित आवेदन के सापेक्ष 6644 निर्माणाधीन है।

हरेला पर्व पर लक्ष्य निर्धारित कर वृक्षारोपण करें– सीएम

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने हरेला पर्व पर आगामी 16 जुलाई को सभी जिलाधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर पौधारोपण करने के भी निर्देश दिए। उन्होने कहा कि यह एक सांस्कृतिक पर्व है, लोगों को इसके साथ जोड़ते हुए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाय। इसके साथ ही हरेला में लगाए जाने वाले पौधों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। उन्होने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने जिलों में कम से कम एक नदी/वॉटर बॉडी/तालाब को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य ले। नैनीताल में सूखा ताल को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखे। इस सीजन में वृक्षारोपण अभियान ऐसी नदियों को ध्यान में रखते हुए किया जाय।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि बागेश्वर जिले में दालचीनी की खेती की अच्छी संभावनाएं हैं, यहां पर दालचीनी क्लस्टर विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। यहां पर श्रीलंका पैटर्न दालचीनी क्लस्टर विकसित किए जाएं। कपकोट में ऑफ सीजन आमो की खेती की अच्छी संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में काली इलायची की खेती की एक बेल्ट विकसित की जा सकती है। साथ ही प्रसंस्करण तंत्र भी विकसित करना होगा।

बागेश्वर में कलना गदेरा को पुनर्जीवन हेतु चुना गया है जहाँ लगभग २–३ लाख पौधे लगाए जाएँगे। जिलाधिकारी बागेश्वर ने अंकुरण कार्यक्रम जड़ी बूटी, दालचीनी और अन्य मसालों के लिए, शहतूत के प्रोत्साहन के लिए शुरू किया है। देहरादून में सुस्वा नदी एवं हरिद्वार में रानीपुर रो नदी को पुनर्जीवन हेतु चुना गया है। पौड़ी में नयार नदी को चुनने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने जिला अधिकारी पौड़ी को 16 जुलाई को 50 हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया। मुख्य विकास अधिकारी देहरादून ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आगामी 16 जुलाई को 25 हजार पेड़ों का वृक्षारोपण पूरे जिले में किया जाएगा तथा इस पूरे मौसम में सात लाख पेड़ लगाए जाएंगे।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एस0 रामास्वामी, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्धन, श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव मुख्यमंत्री श्री अमित नेगी, सचिव श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मो0–7055007009

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 13 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(07/58)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सुबह 10:00 बजे आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र सचिवालय का औचक निरीक्षण किया।

उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से सभी जिलों में भारी वर्षा के बाद अद्यतन स्थिति का विवरण लिया। अधिकारियों ने बताया कि चार धाम मार्ग पूरी तरह खुले हुए हैं और जिलाधिकारियों द्वारा संवेदनशील स्थानो पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा इंतजामात के साथ यात्रा को रेग्युलेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने भारी वर्षा, लैंड स्लाइडिंग तथा बिजली गिरने से कहां कितना–कितना नुकसान हुआ है इसका विवरण भी देखा।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 13 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(07/57)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार देर सायं मुख्यमंत्री आवास पर इण्डो–यूरोपियन कोर्पोरेशन सेंटर के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर इण्डो–यूरोपियन कोर्पोरेशन सेंटर के साथ इण्टीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शिक्षा, पर्यटन, कृषि, वेस्ट मेनेजमेंट पर कार्य करने हेतु चर्चा की गई। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने कहा कि यूरोपीय देश आस्ट्रिया, स्विटजरलेण्ड, जर्मनी की भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखण्ड से मिलती–जुलती है। यदि शिक्षा, पर्यटन एवं कृषि के क्षेत्र में इन यूरोपियन देशों के साथ समन्वय से कार्य किया जाए तो इन क्षेत्रों में उत्तराखण्ड के समग्र विकास में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के हिसाब से पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि पलायन को रोकने के लिए गांवों को मॉडल ग्रामों के रूप में विकसित किया जाना जरूरी है जहां आधुनिक खेती के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रतिनिधिमण्डल के लोगों की सम्बन्धित विभागीय सचिवों से एक बैठक की जायेगी। प्रतिनिधिमंडल में आस्ट्रिया के श्री कृष्टयानमान, जर्मनी के श्री अंजनी कुमार राय के साथ तपोवन ऋषिकेश के श्री कृष्णायोगी एवं कुंजापुरी के श्री राजेन्द्र भण्डारी भी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।